

प्रेषक,

विनोद फोनिया,

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,

उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक, 01 ^{अगस्त} जुलाई, 2008

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत "सी" ग्रेड सेब कय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-107/खा0प्र0(उद्योग)/सेब/बा0ह0यो0/2008-09 दिनांक 02 जून, 2008 तथा निदेशक (सहकारिता), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-L15016/14/2008 M.P.S, दिनांक-14 जुलाई, 2008 (छाया प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड के सेब उत्पादक क्षेत्रों के कृषकों/उद्यानपतियों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदत्त किये जाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में योजनान्तर्गत लगभग 1500 मैटन "सी" ग्रेड सेब कय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उपरोक्त योजना के अन्तर्गत "सी" ग्रेड सेब फलों का समर्थन मूल्य रु0-4.50(रु0 चार रुपये पचास पैसे मात्र) प्रति किग्रा0 निर्धारित किया जाता है।
- 2- फलों का कय/विकय जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में कुमाँयू मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल द्वारा तथा जनपद देहरादून, उत्तरकाशी एवं चमोली में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, देहरादून द्वारा किया जायेगा।
- 3- कय किये जाने वाले "सी" ग्रेड सेब फल का न्यूनतम आकार 45 मि0मी0 व्यास का होना चाहिए, तथा प्रजाति के अनुसार उनमें रंग आ गया हो, एवं फल सड़े, कटे, गले, नहीं होने चाहिए।
- 4- सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा सेब फलों को उपार्जित कर सीधे खुले बाजार/मण्डियों में और राज्य में स्थित प्रसंस्करण इकाईयों को भी विकय किया जायेगा।
- 5- कार्यदायी संस्थाओं को फलों के कय-विकय में निहित सभी overhead व्यय हेतु रु0-112.50 प्रति कुन्तल अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।
- 6- फलों के उपार्जन हेतु दोनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों में निम्न स्थानों पर कय/संग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे :-

जनपद का नाम	प्रस्तावित कय/संग्रह केन्द्र	कार्यदायी संस्था
1	2	3
नैनीताल	रामगढ़, पहाडपानी, भटेलिया, हरतोला, मुक्तेश्वर, धानाचूली।	कुमाँयू मण्डल विकास निगम
अल्मोड़ा	शहरफाटक।	लि0, नैनीताल।

देहरादून	त्यूनी,कोटी,काथियान।	गडवाल मण्डल विकास निगम देहरादून।
चमोली	हेलंग,जोशीमठ,तपोवन, कैलाशपुर,जेलम,मलारी।	
उत्तरकाशी	नौगाँव,बडकोट,सॉकरी,नैटवाड,चिन्यालीसौड़ हर्षिल,आराकोट।	

- 7- संग्रह केन्द्रों की संख्या व स्थान कार्यदायी संस्थाएँ सेब फलों की उपलब्धता के अनुसार घटा-बढ़ा सकते हैं।
- 8- यह योजना केवल फल उत्पादक कास्तकारों के लिए लागू होगी, ठेकेदार व बिचौलिये इस योजना में आच्छादित नहीं होंगे। यह सुनिश्चित करना कार्यदायी संस्थाओं तथा सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा, कि केवल सहकारी समितियों व कृषक संगठनों अथवा सीधे फल उत्पादक कृषकों से ही उपार्जन/कय किया जाये।
- 9- फल उत्पादकों को भुगतान एकाउन्ट पेई बैंक या बैंक एडवाइस के माध्यम से किया जायेगा।
- 10- तुड़ाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन किया के परिणामस्वरूप वजन में कमी आती है, अतः वजन में आने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए कय के समय तौल में 2.5 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।
- 11- निदेशक, उद्यान, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा चयनित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- 12- दोनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित स्थानों पर अस्थाई रूप से कय/संग्रह केन्द्रों की मूलभूत व्यवस्थाएँ एवं कार्मिकों की तैनाती समयबद्ध रूप से कर ली जाय।
- 13- इस कार्य में सहयोग हेतु कार्यदायी संस्थाओं को सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा निकटस्थ उद्यान सचल दल केन्द्र पर कार्यरत कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 14- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फलों के उपार्जन का कार्य दिनांक 01 अगस्त, 2008 से दिनांक 31 अगस्त, 2008 की अवधि में किया जायेगा, परन्तु उक्त अवधि के उपरान्त भी यदि चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड सेब फलों की उपलब्धता हो, तो तदनुसार उपार्जन अवधि अग्रेत्तर विस्तारित किये जाने हेतु तथ्यात्मक प्रस्ताव प्राथमिकता से शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- 15- फलों के विक्रय से प्राप्त आय को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।
- 16- योजना के संचालन में राज्य सरकार को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 50 प्रतिशत एवं शेष 50 प्रतिशत क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध के अधीन की जायेगी कि सेब के कय-विक्रय में कुल क्षति उपार्जन लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 17- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड सेब की उपलब्धता को देखते हुए उक्त निर्धारित सीमा तक सेब कय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की माँग प्रस्तुत किये जाने पर कार्यदायी संस्थाओं को यथाआवश्यक धनराशि अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।



- 18-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सेब क्रय किये जाने की साप्ताहिक प्रगति विवरण, प्रचलित बाजार भाव सहित नियमित रूप से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 19-उक्त योजना के संचालन में होने वाले व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-0113-बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था से किया जायेगा, जो कि शासनादेश संख्या-418/XVI/08/7(24)/08, दिनांक-21 अप्रैल, 2008 द्वारा पूर्व में ही आपके निवर्तन में रखी जा चुकी है।
- 20-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-143(P)/XXVII-4/2008 दिनांक-31 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या-979/XVI/08/5(134)/05, तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक(सहकारिता), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-14 जुलाई, 2008 के क्रम में।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० देहरादून/कुमायूँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल को इस आशय से कि, योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड सेब की उपलब्धता को देखते हुए सेब क्रय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की माँग का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर निदेशक, उद्यान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/चम्पावत/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
- 4- उप निदेशक, उद्यान, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 7- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8- जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/चम्पावत/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०एस०पाण्डे)
अपर सचिव।